ISBN: 978-81-974088-0-9

5. वर्तमान समाज एवं दिव्यांग बालक की शैक्षिक समस्याएं

श्रीमती ममता पांडे

सहायक प्राध्यापक,
स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ़ एजुकेशन,
नरदाहा रायपुर छत्तीसगढ़.

विकलांगता क्या है?

विकलांगता शरीर या मन की कोई ऐसी स्थिति (क्षीणता) है, जो व्यक्ति के लिए कुछ निश्चित गतिविधियां करना (गतिविधि सीमा) तथा अपने आसपास की दुनिया के साथ अंतःक्रिया करना (भागीदारी प्रतिबंध) कठिन बना देती है।

विकलांगताएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि वे जो किसी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं:

- दृष्टि
- आंदोलन
- सोच
- याद आती
- सीखना
- संचार
- सुनवाई
- मानसिक स्वास्थ्य
- सामाजिक रिश्ते

हालाँकि "विकलांग लोग" कभी-कभी एक ही आबादी को संदर्भित करते हैं, लेकिन यह वास्तव में लोगों का एक विविध समूह है जिसकी ज़रूरतें बहुत विस्तृत हैं। एक ही तरह की विकलांगता वाले दो लोग बहुत अलग-अलग तरीकों से प्रभावित हो

सकते हैं। कुछ विकलांगताएँ छिपी हुई हो सकती हैं या उन्हें देखना आसान नहीं हो सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकलांगता के तीन आयाम हैं:

(1) किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना या कार्य, या मानसिक कार्यप्रणाली में हानि ; हानि के उदाहरणों में अंग की हानि, दृष्टि की हानि या स्मृति हानि शामिल है।

(2) गतिविधि सीमित होना , जैसे देखने, सुनने, चलने या समस्या सुलझाने में कठिनाई।

(3) सामान्य दैनिक गतिविधियों में भागीदारी पर प्रतिबंध , जैसे काम करना, सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होना, तथा स्वास्थ्य देखभाल और निवारक सेवाएं प्राप्त करना।

भारत ने अपनी नई शिक्षा नीति (२०२०) की घोषणा की है। देश में शिक्षा योजना और लेन-देन में एक आदर्शबदलावप्रयास करता है। जबकि स्कूली शिक्षा में विकलांग बच्चों की समान भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यह मानता है कि हमारे समाज में सभी कमजोर समूहों में विकलांग बच्चों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और यह कि एक समूह या दूसरे पर ध्यान केंद्रित करके एक समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

विकलांग लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

विकलांगता के साथ जीना चुनौतियों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत करता है जो भौतिक दुनिया से परे तक फैला हुआ है। जबकि पहुँच और समावेशिता के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, विकलांग व्यक्तियों के लिए कई बाधाएँ बनी हुई हैं। यह ब्लॉग विकलांग लोगों के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों का पता लगाएगा, और उन बाधाओं पर प्रकाश डालेगा जो समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधा डालती हैं।

शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के सामने कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं?

सीमित पहुंच:

सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और इमारतों तक पहुँच विकलांग लोगों के लिए एक सतत चुनौती बनी हुई है। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और सार्वभौमिक रूप से डिज़ाइन किए गए वातावरण की कमी अक्सर बाधाएँ पैदा करती हैं, जिससे विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता और स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।

सामाजिक कलंक और भेदभाव:

विकलांगता के बारे में पूर्वाग्रह और गलत धारणाएँ विकलांग लोगों के सामाजिक हाशिए पर जाने में योगदान करती हैं। रूढ़िवादिता उनके शिक्षा, रोजगार और सामाजिक एकीकरण के अवसरों में बाधा डाल सकती है, जिससे बहिष्कार और अलगाव का चक्र चलता रहता है।

शैक्षिक बाधाएं:

समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विधायी प्रयासों के बावजूद, शैक्षणिक संस्थानों में बाधाएँ बनी हुई हैं। दुर्गम सुविधाएँ, उचित आवास की कमी और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी विकलांग छात्रों के सामने आने वाली शैक्षणिक चुनौतियों में योगदान करती हैं।

रोजगार असमानताएँ:

विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरी का बाजार विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भेदभाव, दुर्गम कार्यस्थल और सुविधाओं की कमी अक्सर उनके रोजगार के अवसरों को सीमित कर देती है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए नियोक्ताओं और नीति निर्माताओं दोनों की ओर से एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होती है।

स्वास्थ्य देखभाल असमानताएँ:

विकलांग लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच से समझौता किया जा सकता है। बाधाओं में स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की भौतिक दुर्गमता, सुलभ जानकारी

की कमी और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं की उपेक्षा शामिल हो सकती है। विकलांग व्यक्तियों की समग्र भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस अंतर को पाटना आवश्यक है। यदि आप किसी भी मोटर विकलांगता के लिए उन्नत देखभाल और उपचार की तलाश कर रहे हैं, तो कोयंबटूर में सर्वश्रेष्ठ आर्थोपेडिक अस्पताल के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (२०१६)

"समावेशी शिक्षा" का अर्थ शिक्षा की एक प्रणाली है जिसमें विकलांग और बिना विकलांग छात्र एक साथ सीखते हैं और शिक्षण और सीखने की प्रणाली को विभिन्न प्रकार के विकलांग छात्रों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है।" धारा १६ के अनुसार, "उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थान विकलांग बच्चों को समावेशी शिशिक्षा प्रदान करें।"

"समावेशी शिक्षा" का अर्थ शिक्षा की एक प्रणाली है जिसमें विकलांग और बिना विकलांग छात्र एक साथ सीखते हैं और शिक्षण और सीखने की प्रणाली को विभिन्न प्रकार के विकलांग छात्रों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है।" धारा १६ के अनुसार, "उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त स

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (२००९)

इसने गंभीर और बहु-विकलांग बच्चों को गृह आधारित शिक्षा का विकल्प चुनने का अधिकार दिया। इस कानून ने १९९५ के विकलांग व्यक्ति अधिनियम का भी संदर्भ दिया, इस प्रकार कुछ अस्पष्टता छोड़ दी ,कि विकलांग बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा। विशेष विद्यालयों की स्थिति पर इसकी चुप्पी का मतलब था कि विकलांग छात्रों की शिक्षा विभिन्न मंत्रालयों के अधीन आती रही।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (२०२०) - प्रमुख पहलू

जबकि नीति आरटीई अधिनियम के समर्थन में मजबूत नहीं है, यह पूरी तरह से

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधानों का समर्थन करती है, और "स्कूशिक्षा के संबंध में अपनी सभी सिफारिशों का समर्थन करती है" ,और वादा करती है कि ईसीसीई और में विकलांग बच्चों को शामिल करने और समान भागीदारी स्कूली शिक्षा प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

विकलांग छात्र ''सोशिओ इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेड ग्रुप्स' (एसईडीजी) का हिस्सा हैं, जो नीति द्वारा गढ़ा गया एक नया शब्द है। SEDGs"लिंग पहचान (विशेष रूप से महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति), सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक), भौगोलिक पहचान (जैसे के छात्र) गाँव, छोटे शहर और महत्वाकांक्षी जिले), विकलांग (सीखने की अक्षमता सहित), और सामाजिक-आर्थिक स्थितियां (जैसे प्रवासी समुदाय, कम आय वाले परिवार, कमजोर परिस्थितियों में बच्चे, तस्करी के शिकार या उनके बच्चे, शहरी क्षेत्रों में बाल भिखारियों सहित अनाथ, और शहरी गरीब)।

एनईपी विकलांग छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों पर केंद्रित है। विकलांग बच्चों को कक्षाओं में अधिक आसानी से एकीकृत करने और शिक्षकों और साथियों के साथ जुड़ने में मदद करने के लिए, सहायक उपकरण और उपयुक्त प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरण, साथ ही साथ पर्याप्त और भाषा-उपयुक्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

विकलांगता समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ:

लगातार कम नामांकन:

यूडीआईएसई डेटा का विश्लेषण और वर्तमान में यूडीआईएसई+ डेटा ने हमें लगातार स्कूली शिक्षा की स्थिति की एक तस्वीर दी है। २०१८-२०१९ का UDISE+ डेटा हमें बताता है कि भारत में देश के विभिन्न राज्यों में २४,७८,५३,६८८ बच्चों के साथ १५,५१,०००स्कूल थे। इनमें से २१,१०,८४४ विकलांग छात्र थे। नामांकन में गिरावट या ठहराव की प्रवृत्ति कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों में भी देखी जा सकती है। २०१८-२०१९ में देश भर के केवल २९.४७% स्कूलों में विकलांग बच्चों का नामांकन हुआ है और इसमें व्यापक अंतर-राज्यीय भिन्नता है।

उच्च शिक्षा में विकलांग छात्रों के नामांकन में तेज गिरावट:

जूनियर/उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों में, केवल ०.४८% स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन/विकलांग बच्चों का नामांकन है। स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों का नामांकन प्राथमिक स्तर पर नामांकित विकलांग बच्चों की कुल संख्या का लगभग आधा है।

विकलांग लड़कियों के नामांकन में लगातार लैंगिक असमानता:

२०१४-१५ से २०१८-१९तक विकलांग बच्चों का GPI (लिंग समानता सूचकांक) विकलांग लड़कियों के विकलांग लड़कों के निरंतर लेकिन निम्न अनुपात को इंगित करता है। स्कूली शिक्षा में विकलांग लड़कियों और लड़कों के बीच यह अनुपात ०.७४-०.७ के बीच रहता है।

विशेष विद्यालय:

हमें देश में विशेष स्कूलों की प्रकृति और प्रसार पर कोई आधिकारिक नीति दस्तावेज या योजना नहीं दिखती है और उन्हें किसको संबोधित करना चाहिए, उन्हें किन मानकों का पालन करना चाहिए और उन्हें कैसे विनियमित किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित कई स्कूल, विशेष रूप से विकासात्मक विकलांग छात्रों के लिए अनौपचारिक रूप से चलाए जा रहे हैं, और शिक्षा बोर्ड से जुड़े नहीं हैं। शिक्षा के संगठन में बड़े बदलावों के साथ, जिसका उद्देश्य नीति है, विशेष स्कूलों की स्थिति पर चर्चा एक तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए।

गृह आधारित शिक्षा:

एनईपी २०२० पूरे दिल से समर्थन करता है और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम २००० के तहत गंभीर और कई विकलांग छात्रों के लिए आरटीई अधिनियम में कानूनी विकल्प के रूप में घर आधारित शिक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। हालांकि, जब यह कहता है कि बच्चे पर शिक्षा और पहुंच की जिम्मेदारी डालता है। कि "घर पर आधारित शिक्षा गंभीर और गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए उपलब्ध विकल्प

बनी रहेगी जो स्कूलों में जाने में असमर्थ हैं।"

शिक्षक:

वर्ष २०१८-१९ में केवल ६४२,६०८ शिक्षकों को विकलांग छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि विकलांग शिक्षक प्रणाली में महत्वपूर्ण रोल मॉडल हैं और उनके पास सांकेतिक भाषा या ब्रेल जैसे कौशल होंगे और इन भाषाओं और संचार के तरीकों में पढ़ाने में सक्षम होंगे, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम,के रूप में विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करने

विशेष शिक्षक के लिए संसाधन व्यक्तियों और विशेष शिक्षकों के २०१६ की नियुक्ति के बारे में बात करता है।

विशेष शिक्षक (जिन्हें संसाधन शिक्षक भी कहा जाता है) शिक्षकों का एक समूह है, जिन्हें विकलांग छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। बड़े पैमाने पर भ्रमणकारी मोड में काम करते हुए इन शिक्षकों को अक्सर एसएसए और अब एसएमएसए के तहत बच्चे के समर्थन में स्कूल से स्कूल जाने वाले राज्यों में ब्लॉक स्तर पर तैनात किया गया है।

उन्हें संसाधन केंद्रों पर भी तैनात किया गया है, जो राज्यों ने किया था| उन्हें अन्य शिक्षकों के बराबर नहीं होना चाहिये क्योंकि, उन्हें आमतौर पर कम मानदेय और नौकरी की सुरक्षा के बिना अनुबंध पर लिया जाता है। विभिन्न राज्यों में विशेष शिक्षकों के चयन और नियुक्ति के लिए कोई समान और परिभाषित तंत्र नहीं है।

विकलांग छात्रों के पास आरटीई घटक के तहत स्कूलों के सुदृढ़ीकरण, ब्रेल बुक्स और लार्ज फॉन्ट बुक्स, संसाधन शिक्षकों के लिए वेतन के तहत शौचालय, रॅम्प और रेल के लिए स्वीकृत धनराशि है।

अन्य सभी गतिविधियों जैसे, परिवहन, चिकित्सीय सेवाएं, माता-पिता का अभिविन्यास, लड़कियों के लिए वजीफा, विशेष शिक्षकों के वेतन आदि के लिए| जो विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, ३,५०० रु प्रति बच्चा प्रति वर्ष समावेशी शिक्षा निर्धारित धनराशि से निकाल लिए

पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र:

एनईपी २०२० "सीखने के संकट" को पहचानता है, और पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के साथ-साथ शिक्षकों की शिक्षा और उनके काम की स्थितियों में एक आदर्श बदलाव लाने का प्रयास करता है। भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसे पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा और श्रवण बाधित छात्रों द्वारा उपयोग के लिए राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। जहां संभव और प्रासंगिक हो, स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें पढ़ाया जाएगा।

शिक्षा में लचीलापन और अधिक विकल्प:

छात्र को एक प्रणाली में फिट करने के बजाय, एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया का वादा समावेशी शिक्षा प्रणालियों के विकास के लिए कहीं अधिक अनुकूल है।

सीखने की शैलियों की विविधता, संचार के तरीके और आवश्यकताएं हमारे देश में भाषाओं की विविधता को स्वीकार करते हुए, एनईपी २०२०छात्रों को उनकी घरेलू भाषाओं में सीखने और विभिन्न भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें रखने पर केंद्रित है। यह समझ कि छात्र अपनी घरेलू भाषा में सबसे अच्छा सीखते हैं, विकलांग छात्रों की एक बड़ी संख्या को सक्षम कर सकते हैं। बधिर छात्र बड़े पैमाने पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, बधिर नेत्रहीन छात्र स्पर्शपूर्ण सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे।

छात्रों की व्यक्तिगत ट्रैकिंग: उचित आवास और व्यक्तिगत सहायता के लिए संभावनाएं खोलना

छात्रों के लिए व्यक्तिगत ट्रैकिंग और व्यक्तिगत विकल्पों के लिए २०२० की नीति का वादा विकलांग छात्रों और अन्य लोगों के लिए शिक्षा प्रणाली में उचित आवास और व्यक्तिगत समर्थन की योजना बनाने का अवसर प्रदान कर सकता है। अब यह महत्वपूर्ण है कि योजनाओं और नियमों और विनियमों को इतना लचीला बनाया जाए कि वे व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा कर सकें। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि स्कूलों और राज्यों के पास वह छोटा सा बदलाव करने के लिए संसाधन हों जो

एक बच्चे के लिए शिक्षा के अधिकार को सक्षम बना सकें।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग:

MoE दिशानिर्देश अनुशंसा करते हैं कि पोस्ट (नॅशनल क्युरिकुलम फ्रेमवर्क) NCF-२०२१, नई पुस्तकें एक्सेसिबल डिजिटल फॉर्मेट (ADTs) में होनी चाहिए, ताकि सभी पुस्तकें 'जन्मजात सुलभ" हों। राष्ट्रीय पुस्तक प्रचार नीति और देश भर में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों और पुस्तकालयों के वादे को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब इन दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

शिक्षक की शिक्षा से लेकर छात्र सीखने तक हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर नीति के फोकस के साथ, और निरंतर मिश्रित सीखने की संभावना, हालिया महामारी के आलोक में, आवश्यक सहायक उपकरणों, मोबाइल फोन का उपयोग करने की आवश्यकता और अनुमतियां, उपयुक्त सॉफ्टवेयर, आदि को बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को सक्षम करने और सीखने, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में आवश्यक इनपुट के रूप में देखे जाने की आवश्यकता हो सकती है।

खेल और कला:

स्कूली शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में खेल और कला पर एनईपी के फोकस को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि विकलांग छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

स्कूल की तैयारी: बच्चे को बाहर करने का बहाना नहीं

सार्वभौमिक पहुंच के नीतिगत वादे के साथ, सही उम्र में शिक्षा में शामिल होना भी महत्वपूर्ण है

ताकि बच्चे अपने साथियों के साथ सीख सकें। नीति का उद्देश्य है कि "कक्षा १ में प्रवेश करने वाले सभी छात्र" हैं स्कूल के लिए तैयार", तभी पूरा हो सकता है जब पहुंच पर, परिवारों को तैयार करने पर, पर ध्यान दिया जाए आवास और व्यक्तिगत सहायता के लिए समझना और प्रदान करना जो बच्चे को चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति या बच्चे के लिए सीखने के परिणामों पर भरोसा करने के बजाय बच्चे को पर्याप्त

जानकारी और समर्थन देना।

शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षण:

नीति शिक्षण पेशे की स्थिति को बहाल करने के लिए सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। जैसा कि पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के साथ होता है, नीति शिक्षक की शिक्षा और सशक्तिकरण में व्यवस्थित परिवर्तन का प्रयास करती है। सभी बी.एड. कार्यक्रमों में समय-परीक्षण के साथ-साथ अध्यापन में सबसे हालिया तकनीकों में प्रशिक्षण शामिल होगा, जिसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, बहु-स्तरीय शिक्षण और मूल्यांकन के संबंध में अध्यापन, विकलांग बच्चों को पढ़ाना शामिल है।

बी.एड. पाठ्यक्रम बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन शिक्षकों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे जो शिक्षण के अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, जैसे कि विकलांग छात्रों को पढ़ाना, या स्कूली शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व और प्रबंधन पदों पर, या आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरण के बीच एक चरण से दूसरे चरण में जाने के लिए।

नीति विशेष शिक्षकों की कमी को संबोधित करती है। यह स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षकों की आवश्यकता पर बल देता है।

सुशासन की नीति का वादा:

२०२० एनईपी सुशासन और संसाधनों के कुशल उपयोग का वादा करता है। यह नई मानक सेटिंग, गुणवत्ता मूल्यांकन और नियामक निकायों की स्थापना करता है। यह स्कूल परिसरों के रूप में स्कूलों के प्रशासन के पुनर्गठन को भी सामने लाता है।

स्कूल परिसर: एक अर्ध-स्वायत्त इकाई:

स्कूल परिसर वह इकाई है जो "विकलांग बच्चों के एकीकरण के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगी, क्रॉस डिसेबिलिटी प्रशिक्षण के साथ विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए और जहां कहीं भी आवश्यक हो, विशेष रूप से बच्चों के लिए संसाधन केंद्रों

की स्थापना और स्थापना के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगी।" गंभीर और बहु-विकलांगता के साथ।" ब्लॉक विकास योजनाओं और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के साथ स्कूल परिसर की बातचीत से कमजोर समूहों के साथ-साथ संसाधनों की बहुत सारी स्थानीयकृत योजना और मानचित्रण हो सकता है।

स्कूल परिसर प्रबंधन समितियां:

प्रशासनिक इकाइयों की पुनर्व्यवस्था के साथ अब नीति में एक अतिरिक्त निकाय, स्कूल परिसर प्रबंधन समिति की परिकल्पना की गई है। द स्कूल कॉम्प्लेक्स /क्लस्टर डेव्लपमेंट प्लान (एससीडीपी) वह योजना होगी जिसका उपयोग सभी प्राधिकरण योजना और संसाधन के लिए करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण पहल जो शासन में सुधार करेगी और नीति की भावना को आगे बढ़ाएगी, हर राज्य में बाल भवन की स्थापना है जहां सभी बच्चे कला, खेल और अन्य गतिविधियों में भाग लेंगे और निजी और सरकारी स्कूलों के बीच अच्छी प्रथाओं को जोड़ना और साझा करना

कानूनी ढांचा:

अब यह अनिवार्य है कि भारत में समावेशी शिक्षा के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए कानूनों (आरटीई और आरपीडब्ल्यूडी) को एकीकृत किया जाए। प्रणाली को समावेशी बनाने के लिए प्रासंगिक नियम और अवधारणाएं, जैसे कि उचित आवास, सार्वभौमिक डिजाइन, संचार की व्यापक समझ अब शिक्षा क्षेत्र में आम बोलचाल की होनी चाहिए ताकि योजनाएं और नीति कार्यान्वयन उनसे प्रवाहित हो सकें। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के भारत के अनुसमर्थन के बाद से भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम जैसे कानूनों में संशोधन या पुनर्लेखन नहीं किया गया है।

शिक्षा के विभिन्न स्थल:

विकलांग छात्रों को शिक्षा के इन साइटों के भीतर एक साइट से दूसरी साइट पर और शिक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, व्यक्तिगत समर्थन और उचित

आवास और पसंदीदा माध्यमों और संचार के तरीकों में शिक्षण और सीखने की आवश्यकता है। शिक्षा के एक स्थान से यानि नियमित स्कूल से विशेष स्कूल या एचबीई में प्रवेश करने वाले बच्चों के प्रामाणिक डेटा और इसके विपरीत को कैप्चर किया जाना चाहिए और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए MoE को शिक्षा के इन साइटों में प्रत्येक बच्चे को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली विकसित करना सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षा के इन सभी स्थलों की स्थिति पर नियमित लेखा परीक्षा की एक प्रणाली की जानी चाहिए और जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

विशेष विद्यालय:

विशेष स्कूल उन स्कूलों का एक समूह है जिन पर न तो एनईपी २०२० और न ही कानून विस्तृत है। इन स्कूलों की प्रकृति और कार्य की स्पष्ट परिभाषा के साथ कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। इस तथ्य को देखते हुए कि वे बच्चों के लिए एक कानूनी विकल्प हैं, यह महत्वपूर्ण है कि देश में विशेष स्कूलों की प्रकृति और प्रसार पर एक नीति पत्र या दिशानिर्देश तैयार किए जाएं। सभी मौजूदा विशेष स्कूलों को औपचारिक रूप देने और शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की आवश्यकता है।

गृह आधारित शिक्षा:

जैसा कि एनईपी २०२० द्वारा वादा किए गए मानक और दिशानिर्देश विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए गए हैं, परिवारों को सूचित विकल्प बनाने के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए और कानून के अनुसार बच्चे के विचार सर्वोपरि हैं। एचबीई एक शिक्षा विकल्प होना चाहिए, और शिक्षा के इस रूप के लिए अलग से संसाधन लगाए जाने चाहिए। मानक सेटिंग में शिक्षा के दिनों और घंटों की संख्या, मूल्यांकन और परीक्षा, संसाधन केंद्रों और स्कूलों में सुविधाओं के लिए परिवहन, सैर और बाल भवनों के नियमित दौरे जैसी चिंताएं शामिल होनी चाहिए।

स्कूल से बाहर के बच्चों को वापस स्कूल में लाएं

इस तरह की धारणा के साथ नजर आने वाला व्यक्ति होने वाला था।

स्कूल से बाहर के बच्चों को स्कूलों में लाने की अपनी योजना में राज्य विकलांग छात्रों वाले स्कूलों की पहचान करके शुरुआत कर सकते हैं। फिर वे आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, विशेष स्कूलों और सीबीआर कार्यक्रमों और क्षेत्र के अन्य सामुदायिक समूहों और अन्य जैसे संसाधनों का मानचित्रण कर सकते हैं और बच्चों को वापस और स्कूलों में ला सकते हैं।

विकलांग लड़कियों की पहचान करने और उन्हें स्कूलों में लाने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। चूंकि लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्कूल वापस नहीं आने की संभावना अधिक होती है, इसलिए शिक्षा जारी रखने वाली लड़कियों और विकलांग लड़कियों के महत्व पर सूचना अभियानों में जोर दिया जाना चाहिए। सकारात्मक कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुरक्षा को जोड़ा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्कूलों में विकलांग बच्चों की वापसी और प्रतिधारण की सुविधा हो।

मूलभूत और प्रारंभिक चरण:

राज्यों को इस तथ्य के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है, कि बचपन में विकलांगता अक्सर जन्म के समय या बचपन में होती है और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं को बच्चे के सबसे करीब उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है ताकि वे शिक्षा में और सही उम्र में पूरी तरह से भाग ले सकें। प्रत्येक बच्चे को ट्रैक करना और छोटे बच्चों के पुनर्वास और पुनर्वास आवश्यकताओं को सुगम बनाना समर्थन को सक्षम करने में सर्वोपरि होगा। बच्चे के व्यापक विकास में सहायता के लिए इन अभिसरणों को विभिन्न मंत्रालयों के साथ बनाने की आवश्यकता है।

विकलांग और अन्य कमजोरियों वाली लड़कियां: जुड़वां ट्रैक दृष्टिकोण:

विकलांग छात्रों की शिक्षा की स्थिति के बारे में बहुत कम जाना जाता है, शोध किया जाता है या प्रलेखित किया जाता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित हैं और उन्हें शिक्षा में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि वर्तमान योजनाएं भी इस चौराहे को स्वीकार नहीं करती हैं और विकलांग बच्चे अक्सर इन समूहों के भीतर अदृश्य होते हैं।

समावेशन को अधिकतम करने वाले वातावरण का निर्माण:

भेदभाव के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप, जो अलगाव और अपमान की ओर ले जाते हैं, अब मानकों और गुणवत्ता ढांचे में स्वीकार किए जाने चाहिए यदि विकलांग छात्रों को शिक्षा में बने रहना है। राज्य छात्रों और अभिभावकों से ऑडिट और फीडबैक की नियमित प्रणाली स्थापित कर सकते हैं। इन अंतःक्रियाओं से बड़ी लागत और संसाधनों के बिना और समानता और गरिमा के साथ एक समावेशी शिक्षा प्रणाली सक्षम होगी।

संसाधन शिक्षकों और विशेष शिक्षकों का एक संवर्ग:

समावेशी शिक्षा को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से मजबूत करने के लिए पर्याप्त वेतनमानों और विकास के अवसरों के साथ विशेष शिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों का एक संवर्ग तैयार किया जाना चाहिए ताकि सामान्य शिक्षक के लिए एनईपी की सभी प्रावधान और सुविधाएं उन्हें विस्तारित की जा सकें। भी। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण में विशेषज्ञता रखने वाले शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों पर एनईपी २०२० का दृष्टिकोण संसाधन शिक्षक पर भी लागू होना चाहिए।

विकलांग शिक्षक:

विकलांग छात्रों को शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है और विकलांग शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्यों द्वारा लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। सभी सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने की आवश्यकता है। इस शिक्षक की उचित आवास और समर्थन संरचनाओं की सभी आवश्यकताएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

सामान्य शिक्षकों और अन्य कार्मिकों का प्रशिक्षण:

NEP २०२० अब विकलांग छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित गुणवत्ता वाले शिक्षकों और शिक्षकों पर अधिक जोर देता है। RPWD अधिनियम भी सिस्टम में शिक्षकों और अन्य सभी कर्मियों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है। ईसीसीई से माध्यमिक शिक्षा

तक सभी स्तरों के शिक्षकों के लिए इस तरह के प्रशिक्षण की सामग्री, अवधि और आवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है।

पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र:

अन्य क्षेत्रों की तरह, पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के क्षेत्रों में भी सिस्टम परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि सभी छात्र और साथ ही विकलांग छात्र सीखने के दृष्टिकोण के सार्वभौमिक डिजाइन का उपयोग करके एक साथ अध्ययन करें। एनईपी २०२० के अनुसार शिक्षा के हर चरण के लिए नए पाठ्यक्रम ढांचे को लिखा जा रहा है। उन सभी मौजूदा संस्थानों को फिर से देखने की जरूरत है ,जो वर्तमान में इन संसाधनों का उत्पादन करते हैं और विकलांग छात्रों के लिए विभिन्न भाषाओं में सुलभ सामग्री का उत्पादन करने की उनकी क्षमता को देखते हैं। इसे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर करना होगा।

दुनिया भर में, शिक्षा प्रणाली संघर्ष, आपदा,आर्थिक विषमताओं और तकनीकी सफलताओं से चिह्नित दुनिया की वास्तविकताओं से जूझ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से संभवत: सबसे बड़ी मानवीय आपदा, कोविड १९ महामारी के कारण कहा जाता है ,कि स्कूल को अब एक साल से अधिक समय से व्यावहारिक रूप से ठप होने के कारण, खुद के शिक्षा प्रणालियों को फिर से बनाना पड़ा है|

१अरब से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इनमें से सबसे कमजोर बच्चे हैं - विकलांग बच्चे, बेघर बच्चे और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे। इनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने महामारी के कारण दोनों या एक प्राथमिक देखभालकर्ता को खो दिया है।

ऐसे समय में, एक 'समावेशी शिक्षा' प्रणाली जो हर बच्चे को साथ ले जाती है, बहुत महत्व रखती है। यह वह पैमाना होना चाहिए जिसे हम शिक्षा में किसी भी पुनर्निर्माण और पुन: कल्पना पर लागू करते हैं।

भारत ने अपनी नई शिक्षा नीति (२०२०) की घोषणा की है, जो देश में शिक्षा योजना और लेन-देन में एक आदर्श बदलाव का प्रयास करती है। परिवर्तन के इस क्षण में,

नई नीति और मौजूदा कानूनों के आलोक में समावेशी शिक्षा के दायरे की आलोचनात्मक जांच करना और साथ ही विकलांग छात्रों के सामने आने वाली बाधाओं को इंगित करना महत्वपूर्ण है, ताकि नई योजनाएं उन्हें ध्यान में रख कर बना सकें।

जबकि स्कूली शिक्षा में विकलांग बच्चों की समान भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, कि विकलांग बच्चों का प्रतिनिधित्व हमारे समाज के सभी कमजोर समूहों में किया जाता है, और यह कि एक समूह या दूसरे पर ध्यान केंद्रित करके एक समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि ,शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है, ताकि सभी को समान अवसर मिल सके।

समावेशी शिक्षा का विचार एक देश की शिक्षा प्रणालियों से बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के अलगाव को समाप्त करने के साथ शुरू हुआ। अब यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का एक दृष्टिकोण बन गया है जिसमें सभी शामिल हैं और उन सभी के लिए समान भागीदारी को सक्षम बनाता है ,जो शिक्षा प्रणाली में उनकी भागीदारी में कमजोर थी। अलगाव से एकीकरण तक शिक्षा की अवधारणाओं का विस्तार और फिर सभी के लिए समावेशी शिक्षा प्रणाली, विकलांगता के बारे में सोच में बड़े बदलावों के साथ प्रतिच्छेद करता है,।

विकलांग व्यक्तियों को समाज के भीतर समान अधिकारों के धारकों के रूप में स्थापित किया। समाज की हर संस्था को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि जहा समान भागीदारी संभव हो। विकलांग व्यक्ति को अब केवल एक विकलांग व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक समाज में अन्य लोगों के समान देखा जाता है, और जिसकी जीवन के सभी पहलुओं में भागीदारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य सभी प्रकार की बाधाओं से प्रभावित होती है।

"विकलांग व्यक्तियों में वे लोग शामिल हैं जिनके पास दीर्घकालिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि है जो विभिन्न बाधाओं के साथ बातचीत में दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।"

आजीवन सीखने के वादे के साथ, यह ऐसी रणनीतियां तैयार करता है जो समावेशी शिक्षा प्रणालियों में विकलांग छात्रों के शिक्षा के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण हैं, इनमें अन्य शामिल हैं:

- निःशक्त बच्चों को नि:शुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा या निःशक्तता के आधार पर माध्यमिक शिक्षा से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए|
- व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उचित आवास|
- विकलांग व्यक्तियों को उनकी प्रभावी शिक्षा की सुविधा के लिए सामान्य शिक्षा प्रणाली के भीतर आवश्यक सहायता प्राप्त करने के लिए|
- पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप शैक्षणिक और सामाजिक विकास को अधिकतम करने वाले वातावरण में प्रभावी व्यक्तिगत समर्थन उपाय प्रदान किए जाने चाहिए।

पूर्ण समावेशन के लिए अन्य महत्वपूर्ण कारक कुछ विकलांग छात्रों के लिए संचार, पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों की पहचान हैं। ब्रेल, वैकल्पिक लिपि, संचार के संवर्धित और वैकल्पिक तरीके, जीवन कौशल अभिविन्यास और गतिशीलता कौशल, सांकेतिक भाषा के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। जो छात्र अंधे, बहरे है ।

उन्हें ऐसे वातावरण प्रदान किया जाए कि शैक्षणिक और सामाजिक विकास अधिकतर हो ।" विकलांग शिक्षक जानते हैं कि स्पर्श मोड का उपयोग करके कैसे पढ़ाना है और ब्रेल और सांकेतिक भाषा का उपयोग करना समान रूप से महत्वपूर्ण है यदि छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाना है।

समावेशी शिक्षा के लिए "कानून, नीति, और शिक्षा के वित्तपोषण, प्रशासन, डिजाइन, वितरण और निगरानी केलियों तंत्र में शिक्षा प्रणा के गहन परिवर्तन की आवश्यकता है।"

शिक्षा के लेन-देन के तरीकों में समान रूप से परिवर्तन की आवश्यकता है: "शैक्षिक की संस्कृतियां संस्थानों, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, सभी छात्रों की पूर्ण भागीदारी के लिए नीतियां, शिक्षकों और अन्य कर्मियों के प्रशिक्षण और बड़े पैमाने पर माता-पिता और समुदाय के साथ इंटरफेस।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (२०१६)

यूएनसीआरपीडी के अनुसमर्थन के आठ साल बाद, और विकलांगता समूहों से मजबूत और निरंतर वकालत के बाद, भारत को २०१६ में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) मिला। यह कानून पहली बार "समावेशी शिक्षा" को परिभाषित करता है, जो भारत में विकलांगता क्षेत्र की लंबे समय से मांग है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम कई अवधारणाओं और शर्तों को लाता है ,जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप समावेश और विकलांगता प्रवचन में एक आदर्श बदलाव को दर्शाता है।

यूएनसीआरपीडी की तरह, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता की पहले की चिकित्सा धारणा से बहुत अलग तरीके से परिभाषित करता है: "विकलांग व्यक्ति का अर्थ दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति है, जो बाधाओं के साथ बातचीत में, उसके पूर्ण और दूसरों के साथ समान रूप से समाज में प्रभावी भागीदारी।"

कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समूह। इसके अलावा, रक्त विकार जैसे थैलेसीमिया, हीमोफिलिया और सिकल सेल रोग वाले लोग भी शामिल हैं। मानसिक बीमारी और बहु-विकलांगता ,अन्य स्थितियां हैं। मल्टीपल स्केलेरोसिस और पार्किंसन रोग जैसी पुरानी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी नए कानून का हिस्सा हैं।

कानून, बाधा शब्द को "संचार, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, संस्थागत, राजनीतिक, सामाजिक, मनोवृत्ति या संरचनात्मक कारकों सहित किसी भी कारक के रूप में परिभाषित करता है, जो समाज में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को बाधित करता है।"

भारत में 'समावेशी शिक्षा' शब्द का प्रयोग अभी तक केवल विकलांग बच्चों की शिक्षा के संबंध में ही किया जाता रहा है, और इसे बड़ी शिक्षा योजना - सर्व शिक्षा अभियान योजना, और फिर समग्र शिक्षा अभियान के एक अलग तत्व/कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है। योजना २०१६ तक स्पष्ट परिभाषा के बिना इस शब्द का उपयोग किया गया है, जब विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम ने इस शब्द को

अधिक सिस्टम दृष्टिकोण के साथ परिभाषित किया है:

शिक्षा तक पहुंच में व्यापक भेदभाव को स्वीकार करते हुए, धारा १६ राज्य को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है:

विकलांग छात्रों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश देना और दूसरों के साथ समान रूप से खेल और मनोरंजन गतिविधियों के लिए शिक्षा और अवसर प्रदान करना;

व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास प्रदान करें;

पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप शैक्षणिक और सामाजिक विकास को अधिकतम करने वाले

वातावरण में व्यक्तिगत या अन्यथा आवश्यक सहायता प्रदान करना;

छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर यह ध्यान शिक्षा प्रणालियों में छात्रों की आवश्यकताओं की महान विविधता को पहचानता है। विकलांग छात्रों के लिए, उचित आवास (अर्थात शिक्षा में भाग लेने के लिए छात्रों के लिए आवश्यक छोटे व्यक्तिगत परिवर्तन) गैर-भेदभाव का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और इसे दान के अधिकार के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।

विद्यालय में और विद्यालय के लिये पहुंच:

स्कूल जाना और स्कूल के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में सक्षम होना, शिक्षा के हर पहलू में भाग लेना विकलांग छात्रों के शिक्षा के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धारा १६ "विकलांग बच्चों और विशेष रूप से उच्च समर्थन की जरूरत वाले बच्चों और उनके परिचारकों के लिए परिवहन के प्रावधान" के साथ-साथ "स्कूल भवनों, परिसरों और विभिन्न सुविधाओं की पहुंच" का वादा करती है। विकलांग छात्रों के शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने वाले अन्य खंड **विकलांग छात्रों के शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने वाले कानून** के अन्य वर्गों में सार्वभौमिक डिजाइन, उचित आवास, भेदभाव, साथ ही उच्च समर्थन आवश्यकताओं की अवधारणा शामिल हैं।

बाल केंद्रित शिक्षा और सतत और व्यापक मूल्यांकन:

बाल केंद्रित शिक्षा, पाठ्यक्रम की स्पष्ट सेटिंग जो पूर्ण शारीरिक और मानसिक सक्षम बनाती है

बच्चे के विकास के लिए आवश्यक सभी शिक्षण और शिक्षण सामग्री प्रदान करने की प्रतिबद्धता

बच्चों को शामिल करने के लिए निरंतर और व्यापक मूल्यांकन महत्वपूर्ण विचार हैं| जिसमें

छात्रों की विविधता जिनके पास कई अलग-अलग क्षमताएं हो सकती हैं।

महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में माता-पिता और समुदाय:

स्कूल मैनेजमेंट कमिटी (एसएमसी) में स्कूल के बाहर के माता-पिता और अन्य लोगों की भागीदारी से कई हितधारकों को समुदाय में बच्चों की शिक्षा में हिस्सेदारी मिलती है। तथ्य यह है कि एसएमसी स्वयं समावेशी हैं और महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को शामिल करना अनिवार्य है, सभी बच्चों को शामिल करने की दिशा में एक अतिरिक्त लाभ है। असम जैसे कुछ राज्यों ने विकलांग बच्चों के माता-पिता को भी अपने नियमों में एसएमसी के सदस्यों के रूप में शामिल किया है।

शिक्षक और अन्य कार्मिक:

- समावेश और समानता शिक्षक शिक्षा का एक प्रमुख पहलू बन जाएगा (और स्कूलों में सभी नेतृत्व, प्रशासनिक और अन्य पदों के लिए प्रशिक्षण)

- क्रॉस-डिसएबिलिटी ट्रेनिंग के साथ विशेष शिक्षकों की भर्ती, और जहां भी जरूरत हो, संसाधन केंद्रों की स्थापना के लिए, विशेष रूप से गंभीर या कई विकलांग बच्चों के लिए। सीखने की अक्षमताओं सहित विशिष्ट विकलांग बच्चों को पढ़ाने के तरीके के बारे में शिक्षकों को ज्ञान होना चाहिए |

- काउंसलर और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सिस्टम में जोड़ा जाएगा |

स्कूल परिसर को शासन की इकाई के रूप में लेना:

स्कूल परिसरों को विकलांग बच्चों के एकीकरण के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार शासन की इकाइयाँ हैं।

वे सभी विकलांग बच्चों को आवास और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समर्थन तंत्र प्रदान करने और कक्षा में उनकी पूर्ण भागीदारी और समावेश सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे और उनका समर्थन करेंगे। विशेष रूप से, यह कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी स्कूल गतिविधियों पर लागू होगा।

शिक्षा की विभिन्न साइटों में विकलांग छात्रों की भागीदारी:

भारत में विकलांग छात्रों का शायद एकमात्र समूह है, जिन्हें नीति और कानून दोनों द्वारा वैध साइटों की एक श्रृंखला में शिक्षित किया जाना है।

गंभीर और बहु-विकलांगता वाले शिक्षार्थियों के पुनर्वास और शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए संसाधन केंद्र और उच्च गुणवत्ता वाली घरेलू स्कूली शिक्षा और कौशल प्राप्त करने में माता-पिता की सहायता करना।

पाठ्यचर्या की रूपरेखा और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए एक मिशन:

आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए एक 'राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना इस स्पष्ट उद्देश्य के साथ की जाएगी कि प्रत्येक बच्चे को मानक ३ द्वारा मूलभूत संख्यात्मकता और साक्षरता प्राप्त होगी। बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (एनसीपीएफईसीई) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा एनसीईआरटी द्वारा ८ वर्ष की आयु २५ तक दो भागों में विकसित की जाएगी, अर्थात् ०-३ वर्ष के बच्चों के लिए एक उप-ढांचा और ३-८-वर्ष के बच्चों के लिए एक उप-ढांचा। NCFSE (स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा) NCERT द्वारा सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद तैयार की जाएगी।

स्वास्थ्य और पोषण पर फोकस:

एनईपी २०२० वादा करता है कि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) के माध्यम से संबोधित किया जाएगा

- स्वस्थ भोजन: बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ एक साधारण लेकिन ऊर्जावान नाश्ता दिया जाएगा
- सभी स्कूली बच्चों को नियमित स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा, विशेष रूप से स्कूलों में १०० % टीकाकरण के लिए और इसकी निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे।
- स्कूली शिक्षा प्रणाली में अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं और सामुदायिक भागीदारी का परिचय।

शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास:

प्रत्येक शिक्षक के चरण के भीतर कई स्तरों के साथ कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन की योग्यता-आधारित संरचना प्रस्तावित है।राज्यों को सहकर्मी की समीक्षा, उपस्थिति, प्रतिबद्धता, निरंतर व्यावसायिक विकास के घंटे, और सेवाओं के अन्य रूपों या शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) के आधार पर प्रदर्शन के उचित मूल्यांकन के लिए कई मापदंडों की एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की आवश्यकता है। शिक्षकों को हर साल कम से कम ५० घंटे के व्यावसायिक विकास में भाग लेना चाहिए।

निष्कर्ष:

विकलांग लोगों को खराब स्वास्थ्य परिणामों का अधिक जोखिम होता है। विकलांग लोगों के बीच स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों की स्पष्ट आवश्यकता है।

विकलांग लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बारे में जानकारी इन और अन्य स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने के लिए आवश्यक है।

चार दक्षताएँ और संबंधित शिक्षण उद्देश्य विकलांगता और स्वास्थ्य असमानताओं के बारे में सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ज्ञान के अंतराल को संबोधित करेंगे। वे विकलांग लोगों के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य परिणामों के बीच संबंधों के बारे में आधारभूत ज्ञान प्रदान करते हैं। दक्षताओं को मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल किया जा सकता है।